भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3035

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

विकसित भारत@2047 के अंतर्गत पहल

†3035. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री मनीष जायसवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वस्तरीय सड़क एवं परिवहन अवसंरचना विकसित करने हेतु विकसित भारत@2047 विजन के अंतर्गत कोई विशिष्ट कार्यनीति या पहल की रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एक्सप्रेसवे, स्मार्ट हाइवे और परिवहन में डिजिटल अवसंरचना की भूमिका सहित उक्त विजन के अंतर्गत किन प्रमुख क्षेत्र/सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है ;

(ग) उक्त दीर्घकालिक अवसंरचना योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में चिन्हित की गई अथवा जिन परियोजनाओं या गलियारों पर कार्य प्रारंभ किया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क अवसंरचना के माध्यम से सृजित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य-दिवसों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर चिन्हित दुर्घटना-प्रवण ब्लैकस्पॉट का ब्यौरा क्या है; और

(च) विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप सड़क और परिवहन अवसंरचना में स्थिरता, नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) अवसंरचना क्षेत्र क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है और तीव्र वृद्धि एवं आर्थिक विकास में योगदान देता है। वर्ष 2025-26 का बजट त्वरित वृद्धि, समावेशी विकास, सुदृढ़ अवसंरचना हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने तथा "विकसित भारत" के विजन को साकार करने हेतु निरंतर सरकारी प्रयासों पर केंद्रित है। तदनुसार, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ देश की संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए पहुंच नियंत्रित राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) / एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, इसके अलावा राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों / शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर का विकास करने का निर्णय लिया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर यातायात की भीड़ कम हो और जाम/भीड़भाड़ वाले बिंदुओं को कम किया जा सके और पत्तन संपर्कता में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यूनतम दो लेन के पेव्ड शोल्डर मानकों सहित यातायात की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6/8 लेन में अपग्रेड करने की नीति भी

अपनाई है, जिसमें पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर, जहां विकास योजना को भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि पर विचार करके अंतिम रूप दिया जाता है।

सरकार ने कुल 8,391 किलोमीटर लंबाई में पहुंच नियंत्रित राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे का विकास कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें से अब तक 5,110 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। कुल 2,730 किलोमीटर लंबाई के पहुंच नियंत्रित राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे पहले ही चालू हो चुके हैं।

सरकार फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) आधारित यातायात प्रबंधन आदि जैसे डिजिटल अवसंरचना को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। सरकार ने चार लेन और उससे ऊपर के राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है। एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का प्रावधान है, जो राजमार्गों पर होने वाली घटनाओं (यातायात उल्लंघनों सहित) की शीघ्र पहचान करने और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे घटना के दौरान प्रतिक्रिया समय और सड़क सुरक्षा में सुधार होता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किया गया पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरकों में से एक है, जो तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में 35,335 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के अनुमानित 48.87 करोड़ कार्य -दिवस और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनुमानित 57.81 करोड़ कार्य-दिवस सृजित हुए हैं।

(ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित कुल 13,795 दुर्घटना प्रवण स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) में से 11,866 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार तथा 5,324 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार पूरा कर लिया गया है।

(च) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, क्रियान्वयन, संचालन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में स्थिरता को एकीकृत करने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:-

i. राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण हेतु हरित राजमार्ग पहल;
ii. स्ट्रीट लाइटों और अन्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग;
iii. राजमार्ग निर्माण में अपशिष्ट उपयोग, जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, बायो बिटुमेन आदि;
iv. राजमार्ग निर्माण में टिकाऊ सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जैसे स्टील स्लैग, ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलीमर आदि;
v. राजमार्ग नियोजन के दौरान वन्यजीव वास स्थलों का संरक्षण;
vi. अमृत सरोवर और वर्षा जल संचयन आदि।

*****